



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 556]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 9, 2015/भाद्र 18, 1937

No. 556]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 9, 2015/BHADRA 18, 1937

वित्त मंत्रालय

महानिदेशक (रक्षोपाय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2015

विषय : भारत में “600 मिमी. अथवा इससे अधिक चौड़ाई की क्वायल में गैर-अलॉय अथवा अलॉय इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स” के आयात से संबंधित रक्षोपाय जांच के बारे में प्रारम्भिक निष्कर्ष।

सा.का.नि. 690(अ).—सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय इयूटी की पहचान और निर्धारण) नियमावली, 1997 को ध्यान में रखते हुए;

क. प्रक्रिया :

1. भारत में “600 मिमी. अथवा इससे अधिक चौड़ाई की क्वायल में गैर-अलॉय अथवा अलॉय इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स” जिनहें यहां पीयूसी (विचारणाधीन उत्पाद) कहा गया है, के आयात पर रक्षोपाय जांच शुल्क लगाए जाने के बारे में सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय इयूटी की पहचान और निर्धारण) नियमावली, 1997 के अंतर्गत मैसर्स स्टील अथरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड; मैसर्स एस्सर स्टील इंडिया लिमिटेड और मैसर्स जेएसडब्ल्यू स्टील इंडिया लिमिटेड द्वारा मैसर्स लक्ष्मी कुमारन और श्रीधरन अटोर्नी नई दिल्ली के माध्यम से दिनांक 27 जुलाई, 2015 को मेरे समक्ष एक आवेदन दायर किया गया है ताकि पीयूसी के घरेलू उत्पादकों को, भारत में पीयूसी के बढ़े हुए आयात द्वारा होने वाली गम्भीर क्षति/ गम्भीर क्षति की आशंका से बचा जा सके। घरेलू उद्योग ने, विचारणाधीन उत्पाद के बढ़े हुए आयात के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में अत्यधिक गिरावट आने के मद्देनजर अनंतिम रक्षोपाय इयूटी लगाए जाने का भी अनुरोध किया है।

2. उक्त रक्षोपाय नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत अपेक्षाओं को पूरा करने के आशय से आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना को, घरेलू उत्पादकों के प्लांट पर यथा संभव आवश्यक आन-साइट दौरा करके सत्यापित किया गया था। सत्यापन रिपोर्ट का गैर-गोपनीय पाठ पब्लिक फाइल में रखा गया है। इस बात से संतुष्ट होने पर कि नियम 5 की अपेक्षाएं पूरी कर ली गई हैं, भारत में पीयूसी के आयात के संबंध में रक्षोपाय जांच, दिनांक 7 सितम्बर, 2015 के नोटिस के अंतर्गत शुरू की गई थी तथा उसी दिन भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित कर दी गई थी।
3. आरम्भिक नोटिस, दिनांक 7 सितम्बर, 2015 की प्रति और घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के गैर-गोपनीय पाठ की प्रति, सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय इयूटी की पहचान और निर्धारण) नियमावली, 1997 के नियम 6 (2) और 6(3) के अनुसार वाणिज्य से संबंधित केन्द्र सरकार के मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों, मुख्य निर्यातक देशों की सरकारों को भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से तथा घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन में उल्लिखित इच्छुक पार्टियों को भिजवा दी गई थी।
4. उपलब्ध सूचना के अनुसार ज्ञात इच्छुक पार्टियों को प्रश्नोत्तर इस अनुरोध के साथ भिजवा दिए गए थे कि वे नोटिस आरम्भ किए जाने के 30 दिन के भीतर लिखित में अपने मत भिजवा दें।

(ख) **प्रारम्भिक टिप्पणी और महानिदेशक (रक्षोपाय के निष्कर्ष) :**

5. मैंने मामला रिकॉर्ड और घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लिया है और सत्यापन दौरे के रिकॉर्ड भी देख लिए।

**(I) विचारणाधीन उत्पाद (पीयूसी) :**

विचारणाधीन उत्पाद हैं “600 मिमी. अथवा इससे अधिक चौड़ाई के क्वायल में गैर अलॉय और अन्य अलॉय इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट” जिन्हें यहां पीयूसी (विचारणाधीन उत्पाद) के रूप में संदर्भित किया गया है तथा जो टैरिफ शीर्ष 7208 और टैरिफ मद 72253090 के अंतर्गत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 72 के अंतर्गत वर्गीकृत योग्य हैं। आवेदक ने यह दावा किया है कि इन उत्पादों पर हॉट रोल्ड की तरह और आगे कार्य नहीं किया गया है और ये प्राइम अथवा गैर-प्राइम स्थिति में “रोल्ड” एज अथवा “ट्रिम्ड” एज अथवा “स्लिट” एज वाले लौह, अलॉय अथवा गैर-अलॉय के फ्लैट प्रोडक्ट हैं। ये उत्पाद पिकलड अथवा गैर पिकलड (स्टिकन-पास अथवा टेम्परिंग सहित अथवा इसके बिना), स्लिट अथवा गैर स्लिट वाले तथा 600 मिमी. अथवा इससे अधिक सामान्य चौड़ाई वाले हो सकते हैं। ये उत्पाद एस-रोल्ड अथवा थर्मोमैकेनिकली रोल्ड अथवा थर्मोमैकेनिकली कंट्रोल्ड रोल्ड अथवा कंट्रोल्ड रोल्ड हो सकते हैं। इन उत्पादों में रोलिंग से सीधे व्युत्पत रिलीफ पैटर्न हो सकते हैं। ये उत्पाद पिकलिंग, ऑयलिंग रिवाइंडिंग, टेम्पर रोलिंग, हीट ट्रीटमेंट इत्यादि जैसे विभिन्न प्रोसेसिंग चरणों से गुजरे हुए हो सकते हैं।

विचारणाधीन उत्पाद के दायरे में निम्नलिखित को शामिल नहीं किया गया है :

- (क) 600 मिमी. से कम चौड़ाई वाले इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट;
- (ख) एपीआई ग्रेड स्टील;
- (ग) सिलीकॉन इलेक्ट्रिकल स्टील;
- (घ) स्प्रिंग इस्पात गुणवत्ता के इस्पात वाले हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट;
- (ङ) इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट जिन पर इलेक्ट्रोलिटिकल रूप से परत चढ़ाई गई है अथवा जिंक की परत चढ़ाई गई है।
- (च) जिंक की परत चढ़ाए गए अथवा कोट किए गए उत्पाद के अलावा इस्पात के अन्य हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट और
- (छ) जंग रहित इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट

## (II) घरेलू उद्योग :

6. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 6x घरेलू उद्योग को निम्नलिखित अनुसार परिभाषित करती है :

(ख) “घरेलू उद्योग” से अभिप्राय ऐसे उत्पादकों से है –

- i. इसी तरह की कोई मद अथवा भारत में प्रत्यक्ष रूप से प्रतियोगी मद; अथवा
- ii. उसी तरह की मद अथवा भारत में प्रत्यक्ष रूप से प्रतियोगी मद का कुल निर्गत, भारत में उक्त मद के कुल उत्पादन का मुख्य हिस्सा बनता है।

7. यह आवेदन मैसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड; मैसर्स एस्सर स्टील इंडिया लिमिटेड और मैसर्स जेएसडब्ल्यू स्टील इंडिया लिमिटेड द्वारा मैसर्स लक्ष्मी कुमारन और श्रीधरन अटॉर्नी नई दिल्ली के माध्यम से दायर किया गया है। उन्होंने यह दावा किया है कि उनका कुल उत्पादन, भारत में पीयूसी के कुल उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक है और यह देश में विचारणाधीन उत्पाद के भारत के उत्पादन के मुख्य हिस्से को दर्शाता है और अतः उनके पास इस आवेदन को दायर करने का आधार है।

8. रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी के मद्देनजर यह निर्धारित किया जाता है कि आवेदन दायर करने वाले घरेलू उत्पादकों तथा ऐसे उत्पादकों जिन्होंने संगत सूचना उपलब्ध कराई है, का उत्पादन, भारत में उक्त मद के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। तदनुसार वे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 6x के अनुसार घरेलू उत्पादक हैं।

## (III) जांच की अवधि :

9. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975, सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय ड्यूटी की पहचान और निर्धारण) नियमावली, 1997, रक्षोपाय संबंधी करार और जीएटीटी के संगत अनुच्छेद XIX विनिर्दिष्ट रूप से यह परिभाषित नहीं करते कि जांच की अवधि क्या होनी चाहिए। रक्षोपाय उपायों संबंधी विभिन्न मामला कानूनों से यह स्पष्ट होता है कि न तो रक्षोपाय संबंधी घरेलू कानूनों अथवा रक्षोपायों और जीएटीटी के अनुच्छेद 19 के करार में जांच की अवधि के संबंध में विशिष्ट दिशा-निर्देश नहीं है केवल इस तथ्य को छोड़कर कि संगत जांच अवधि पर्याप्त रूप से इतनी लम्बी होनी चाहिए ताकि बढ़े हुए आयात और गम्भीर क्षति के संबंध में निष्कर्ष निकाला जा सके। इस मामले में अन्वेषण की अवधि 2013-14 से 2015-16 (वार्षिकृत) ली गई है जो बाजार निबंधनों और संरक्षण शुल्क के अधिरोपण की आवश्यकता सुनिश्चित हेतु विचारण में लिए जाने के क्रम में पर्याप्त हैं।

## (IV) सूचना का स्रोत:

10. 2013-14 से 2015-16 (प्रथम तिमाही) घरेलू उद्योग द्वारा यथा प्रदत्त आईबीआईएस से ‘पीयूसी’ के लिए संचालनवार आयात डाटा लिया गया है और इसे विश्लेषण हेतु विचारण में लिया गया है। 2011-12 से 2015-16 (प्रथम तिमाही) घरेलू डाटा को घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किया गया है और आवश्यक समझा जाने की सीमा तक इसे इकाइयों में बनाए रखे जाने वाले उत्पाद रिकॉर्ड्स और अन्य रिकॉर्ड्स के आधार पर विभाग द्वारा स्थल-विशेष पर ही दौरे के द्वारा सत्यापित किया गया है।

## (V) प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता

11. घरेलू उद्योग ने गोपनीय आधार पर कुछ सूचना उपलब्ध कराई है और प्रस्तुत की गई सूचना/डाटा पर गोपनीयता की मांग की है। घरेलू उद्योग ने संरक्षण नियमावली 1977 और व्यापार सं. एसजी/टीएन/1/97 दि. 06.09.1997 के प्रावधानों के अनुसार संरक्षण उपाय हेतु आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध करवाए। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने आवेदन फाइल किए जाते समय गोपनीयता की मांग हेतु कारणों को प्रस्तुत किया गया है।

12. संरक्षण नियमावली, 1997 और संरक्षण पर डबल्यूटीओ समझौते का अनुच्छेद 3.2 भी गोपनीयता हेतु उपबंधित किया गया है। आवेदक से ऐसी सूचना प्रकट किया जाना अपेक्षित नहीं हैं जो कंपनी की गोपनीय सूचना है, जिसका प्रकटन कंपनी के व्यावसायिक हितों को गंभीर पूर्वाग्रह का कारक बन सकता है, जो पब्लिक डोमेन में नहीं है और पूर्व में बृहत् रूप में जनता के समक्ष जिसे आवेदक ने प्रकट नहीं किया है। तदुसार घरेलू उद्योग द्वारा यथा प्रदत्त, गोपनीयता मंजूर की गई है।

#### (VI) अभिवर्धित आयात (निरंकुश और संगत स्वरूप में)

13. ‘पीयूसी’ को विभिन्न देशों से भारत में आयात किया गया है। ‘पीयूसी’ के आयात नीचे दर्शाई गई तालिका में अवधि के दौरान संगत शर्तों के साथ-साथ पूर्ण आधार पर एक बढ़ते रूख को दर्शाया गया है:-

वित्तीय वर्ष	कुल आयात (एमटी)	प्रवृत्ति	अखिल भारतीय उत्पादन (एमटी)	उत्पादन के संबंध में आयात का प्रतिशत
2013-14	1292099	100	25510777	5
2014-15	2540114	197	26395795	10
2015-16(प्रथम तिमाही )	844840		6646258	
2015-16(ए)	3379360	262	26585032	13

#### (VII) अप्रत्याशित विकास

14. यह नोट किया गया है कि अप्रत्याशित परिस्थितियों के विश्लेषण हेतु महानिदेशक पर कोई व्यक्त बाध्यता/अपेक्षा नहीं है क्योंकि अप्रत्याशित विकासों के विश्लेषण हेतु अनुसरणित प्रणाली पर भारतीय नियमावली अथवा संरक्षणों पर डबल्यूटीओ समझौता जिसमें प्रणाली जिसका अप्रत्याशित विकासों के निर्णयन के मापदंडों को पूरा किए जाने अथवा उसका अनुसरण किए जाने की प्रणाली के संबंध में कोई निर्धारण भी नहीं किया गया है। तथापि जीएटीटी के अनुच्छेद xix के साथ पठित रक्षोपाय पर समझौते में ‘अप्रत्याशित विकासों’ के परीक्षण हेतु राष्ट्रीय प्राधिकारियों की बाध्यता है, जो घरेलू उद्योग में गंभीर क्षति हेतु प्रशस्त है। यह स्वतः भिज है कि इस निदेशालय द्वारा इसके अन्वेषणों में “अप्रत्याशित विकासों” के मुद्दों को लगातार परीक्षण किया गया है। अतः अप्रत्याशित समझा गया है, जो आयातों की अभिवृद्धि हेतु प्रशस्त है।

15. अर्जेंटीना में अपीलीय निकाय-फुटवियर (ईसी मामला) ने निर्णय किया है कि अप्रत्याशित विकासों के मुहावरे से तात्पर्य अप्रत्याशित विकासों से है। “अप्रत्याशित विकासों” हेतु अपेक्षित है कि विकास जो ऐसी अभिवर्धित मात्राओं और घरेलू उत्पादों हेतु गंभीर क्षति पैदा करने अथवा आशंका रूपी ऐसे निबंधनों के अंतर्गत आयातित किए जा रहे उत्पादों हेतु प्रशस्त हैं ‘अप्रत्याशित’ होना चाहिए। समान मामले में निकाय ने एक जीएटीटी पैनल रिपोर्ट नोट की है जिसमें निर्णय किया है कि टैरिफ परक्रामण के समय विकास अप्रत्याशित होना चाहिए। कोरिया-डेयरी मामले में अपीलीय निकाय ने निर्णय दिया कि अप्रत्याशित विकास जब सदस्य उस बाध्यता को व्यपगत करता है प्रत्याशित अथवा अपेक्षित नहीं है।

16. अर्जेंटीना में अपीलीय निकाय-फुटवीयर (ईसी) ने तब निर्णय दिया कि “अप्रत्याशित विकासों” की अपेक्षा रक्षोपाय उपायों के अधिरोपण हेतु एक प्रथक “निबंधन” को स्थापित नहीं करता है, किंतु “परिस्थितियों” के एक कतिपय सैट को निर्धारित करता है।

17. यूएस-स्टील रक्षोपाय पर पैनल का निष्कर्ष है कि अनेक घटनाओं के सम्मिलन एक अप्रत्याशित विकास के आधार स्वरूप को समेकित कर सकता है। “यूनाईटेड स्टेट्स ने तर्क प्रस्तुत किया कि यूएस डॉलर की मजबूती एक विकास था जो अन्य विकासों अर्थात् एशिया में और पूर्व यूएसआर में मुद्रा संकट और यूनाईटेड स्टेट्स में इस्पात की मांग में लगातार वृद्धि शामिल हैं, मार्केट अन्य घटती मार्केट्स के रूप में अभिवर्धित आयातों हेतु प्रशस्त है।”

18. आवेदक ने इंगित किया कि कई देशों ने जिसमें कि चीन पीआर, रूस और यूक्रेन भी शामिल हैं, में इस्पात निर्माताओं ने विकसित देशों और शेष विश्व द्वारा इस्पात की मांग को पूरा करने की अपार क्षमताओं को विकसित किया है। अधिकांश देश जो पारंपरिक रूप से इस्पात के बड़े आयातक थे, जैसे यूनाईटेड स्टेट्स और यूरोपीय संघ ने इस्पात आयात पर उनकी निर्भरता को घटाया था। इस विकास से चीन पीआर, रूस, यूक्रेन इत्यादि से विकसित देशों को इस्पात का आयात प्रतिकूलतः प्रभावित हुआ। इन देशों में आयातकों को उनके उत्पादन को निपटाने के लिए सोचना पड़ा था। भारत बहुविध कारणों से इन निर्माताओं का स्वाभाविक चयन बना।

19. 31 दिसंबर 2014 तक वैश्विक कच्ची स्टील क्षमता 2351 थी जो कि भारत जैसे देशों जिनमें इसकी काफी मांग हैं, के अधिशेष स्टील के निर्यात के लिए बढ़ती मांग के परिणाम-स्वरूप लगभग 30% द्वारा, वैश्विक मांग की अधिकता से दूर थी।

20. भारत उच्च घरेलू मूल्य तथा अपेक्षतया श्रेष्ठ मांग की संभावना के साथ इन स्टील अधिशेष अर्थव्यवस्थाओं के लिए उनकी अधिक क्षमता को दिशा प्रदान करने के लिए, सदैव एक आकर्षण रहा है।

21. पिछले कुछ वर्षों में, रूस ने भारत में अपना निर्यात बढ़ाया है। प्रतिष्ठित जर्नल स्टील 360 की रिपोर्ट के अनुसार, रूसी स्टील उत्पादक, अपनी कमजोर मुद्रा के कारण भारत में होने वाले अपने निर्यात के लिए उच्च प्राप्ति का अनुभव कर रहे हैं। इन कारणों से भारत में रूस का स्टील का निर्यात बढ़ा है क्योंकि यूरोपीय यूनियन तथा यूक्रेन जैसे पारंपरिक बाजारों ने रूस में अपनी पहुंच बंद कर दी है।

22. उक्रेन मुद्रा हरवना ने 2014 में अकेले करीब 60 प्रतिशत का तीव्र मूल्यव्यापास देखा। यह रूस के हस्तक्षेप के कारण उक्रेन में राजनीतिक अशांति का परिणाम था। उक्रेन में अशांति की लम्बी अवधि के कारण इसकी अर्थव्यवस्था सिकुड़ गई और इसकी मुद्रा यूएस डॉलर को तीव्रता से घट गई। तथापि, रूस के सदृश, उक्रेन मुद्रा में मूल्यव्यापास ने उसके स्टील उत्पादकों/निर्यातकों को सहायक हुआ ताकि वे वैश्विक स्टील बाजार पर और दबाव डालने के लिए अपने न्यून मूल्यांकित निर्यातों को लीवरेज कर सकें। कई अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में यह सुलिखित है कि उक्रेन में कैसे रूस और चीन को ज्वाइन किया है ताकि स्टील मूल्य कम हों और अच्छी मांग के देशों के साथ अपनी अतिरेक स्टील को दिया जाए। यह प्रमाणित है कि उक्रेन यह प्रवृत्ति 2015 में भी जारी रखेगा।

23. चीन पीआर कमजोर घरेलू मांग से गुजर रहा है। अवसंरचना क्षेत्र, विशेषतः हाउसिंग जौकि चीन पी आर में स्टील का सबसे बड़ा उपभोक्ता रहा है, मन्दी से गुजर रहा है। चीनपीआर में विनिर्माता घरेलू बाजार में अपने उत्पादन का और अधिक निपटान नहीं कर सकते। इस स्थिति की अल्प अवधि में अपरिवर्तित रहने की संभावना है और चीन स्टील प्रयोग 2015 और 2016 में 0.5 प्रतिशत की रकारात्मक वृद्धि को रिकॉर्ड करना जारी रखेगा। इसके परिणामस्वरूप भारत जैसे देशों को निर्यात एक सहज चयन है क्योंकि भारत में स्टील की मांग बढ़त पर रही है। चीन पी आर में ऐसे मूलभूत कारकों का परिणाम चीन पी आर से आयातों का अचानक प्रवाह हुआ है।

24. प्रदान किए गए डाटा/ साक्ष्यों का परीक्षण करने पर यह देखा जाता है कि चीन पी आर, रूस और यूक्रेन तथा दूसरे देश विशेषतः भारतीय बाजार में पीयूसी भेज रहे हैं क्योंकि भारत अपेक्षकृत बेहतर मांग संभावनाओं और उच्च घरेलू मूल्यों के साथ अपनी अधिक क्षमताओं को पहुंचाने के लिए इन स्टील अतिरेक अर्थव्यवस्थाओं के लिए आकर्षण रहा है। विश्व स्टील गतिकी में प्रकाशित रिपोर्ट में वर्णन है कि “पहले 2015 के लिए प्रभावित क्षमता आंकड़े कुल 2.05 अरब (बिलियन) टन के लिए, गैर-चीन उद्योग के लिए 1055 मिलियन टन और चीन के लिए 991 मिलियन टन है। वर्ष

2014 में हुए 1.66 बिलियन टन के इस्पात उत्पादन से हम तुलना करते हैं तो पाते हैं कि विश्व की कुल इस्पात निर्माण क्षमता 382 मिलियन टन है। तदनुसार उपर्युक्त बातों और दिए गए साक्ष्य के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रमुख निर्यातक देशों की वर्तमान अतिरिक्त क्षमता और भारत की बढ़ती मांग/पीयूसी की खपत ही इस प्रकार बढ़ते आयात के कारण हैं। अतः यह देखने में आता है कि घरेलू उत्पादन द्वारा बताए गए उपर्युक्त कारण अप्रत्याशित हैं”

#### (VIII) गम्भीर क्षति और गम्भीर क्षति का खतरा :

25. **गम्भीर क्षति :** आवेदक ने यह दावा किया है कि पीयूसी के बढ़ते आयात के कारण पीयूसी के घरेलू उत्पादकों को गम्भीर क्षति हुई है और ऐसी गम्भीर क्षति का खतरा भी बना हुआ है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

(क) **उत्पादन :** घरेलू उत्पादकों का उत्पादन एक ही स्तर पर बना रहा जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

वर्ष	डीआई का उत्पादन (मीटन)	रुख
2013-14	17881187	100
2014-15	17836937	100
2015-16(प्रथम तिमाही )	4456795	
2015-16 (ए)	17827180	100

(ख) **घरेलू मांग में घरेलू उत्पादकों का बाजार हिस्सा :** हाल की अवधि में आवेदकों का बाजार हिस्सा गिरा है। 2013-14 में आवेदकों का बाजार हिस्सा 45 प्रतिशत था जो कि 2015-16 (क) में घटकर 37 प्रतिशत हो गया है। इसी अवधि के दौरान आयात का बाजार हिस्सा 6 प्रतिशत से बढ़कर 12 प्रतिशत हो गया है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

वित्तीय वर्ष	कुल आयात (मी.टन)	डीआई का विक्रय (मी.टन)	अन्य भारतीय उत्पादकों की विक्री (मी.टन)	डीआई की कैपिटिव विक्री (मी.टन)	अन्य की कैपिटिव विक्री (मी.टन)	कुल मांग (मी.टन)	मार्केट शेयर (%)	डीआई आयात
2013-14	1292099	10342565	2994323	4274000	4000724	22903711	45	6
2014-15	2540114	9949214	3298273	5019741	4615864	25423206	39	10
2015-16 (प्रथम तिमाही)	844840	2589929	1065972	1321497	1180681	7002919		
2015-16 (ए)	3379360	10359716	4263888	5285988	4722724	28011676	37	12

(ग) उत्पादकता एवं रोजगार.—इस अवधि के दौरान रोजगार एवं उत्पादकता का रुख एक जैसा रहा है जैसा कि नीचे सारणी से स्पष्ट होता है।

वित्तीय वर्ष	रोजगार की संख्या (सूचकांक)	प्रति कर्मचारी उत्पादकता (मी.टन) (सूचकांक)
2013-14	100	100
2014-15	100	100
2015-16(प्रथम तिमाही)	100	
2015-16(ए)	100	100

घ. क्षमता उपयोग.—इस अवधि के दौरान, जैसा कि नीचे सारणी से विदित है क्षमता उपयोग वही रहा जो 2013-14 से 2015-16 (ए) के दौरान था:

वित्तीय वर्ष	संस्थापित क्षमता (मी.टन)	क्षमता उपयोग (%)
2013-14	23568996	76
2014-15	23568996	76
2015-16(प्रथम तिमाही)	5884372	
2015-16(ए)	23537488	76

(ङ.) लाभ/हानि.—घरेलू उद्योग की लाभप्रदाता 2015-16 (प्रथम तिमाही) में तेजी से कम हुई और घरेलू उद्योग में निम्नलिखित सारणी के अनुसार हानियां दर्ज की:-

वित्तीय वर्ष	लाभ प्रदाता (रूपये/ मी.टन) सूचकांक
2013-14	100
2014-15	135
2015-16(प्रथम तिमाही)	(55)

(च) माल सूची.—निम्न सारणी माल सूची दर्शा रही है 2013-14 में 100 बिन्दुओं से बढ़कर 2015-16 (ए) में 103 बिन्दुओं की तेजी देखी गई।

वित्तीय वर्ष/ तिमाही	माल सूची (मी.टन)	माल सूची (मी.टन) (सूचकांक)
2013-14	636879	100
2014-15	648290	102
2015-16(प्रथम तिमाही)	657099	103

(छ) मूल्य छास.—निम्नलिखित सारणी से यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग पर आयात कीमतों के अनुरूप अपनी कीमतों को कम करने या अपनी कीमतों पर बने रहने का लगातार दबव था। अभूतपूर्व उच्च स्तर पर बढ़े हुए आयातों का प्रवेश ऐसा था कि कीमत कम करने पर भी घरेलू उद्योग अपने उत्पादन/बिक्री और बाजार हिस्सेदारी पर बने रहने में सक्षम नहीं था। इसकी परिणति 2015-16 (प्रथम तिमाही) के दौरान घरेलू उद्योगों के लिए हानियों के रूप में हुई।

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16(तिमाही 1)
बिक्री की लागत (सूचकांकित)	रुपये/ मी.टन	100	97	92
भारित औसत बिक्री उगाही (सूचकांकित)	रुपये/ मी.टन	100	99	84
आयातित माल का मूल्य (सूचकांकित)	रुपये/ मी.टन	100	94	77
लाभ/(हानि) (सूचकांकित)	रुपये/ मी.टन	100	135	(55)

26. उपर्युक्त के मद्देनजर, यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग के वित्तीय पैरामीटरों में सभी ओर से गिरावट आई और घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई और घरेलू उद्योग को आगे और क्षति से बचाने के लिए, सुरक्षोपाय शुल्कों के रूप में तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता है।

27. यह भी देखा गया है कि वर्तमान जांच में भी गंभीर क्षति का जोखिम विद्यमान है जैसा कि उपर्युक्त से विहित है। जांच की अवधि पर आयातों में भारी वृद्धि हुई जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई और सभी संभावनाओं में, पीयूसी के आयात आगे और बढ़ेगे और घरेलू उद्योग के लिए गंभीर क्षति का जोखिम बना रहेगा। घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी 2013-14 में 45 प्रतिशत से घट कर 2014-16 (ए) में 37 प्रतिशत हो गई। जबकि इसी अवधि के दौरान, आयात की बाजार हिस्सेदारी 2013-14 में 6 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 (ए) में 12 प्रतिशत हो गई जो चिंताका कारण है।

### **(IX)बढ़े हुए आयात और गंभीर क्षति या गंभीर क्षति का जोखिम के बीच कारण-संबंध:**

28. कोरिया डेरी पर पैनल ने “कारण निर्धारण” के लिए प्रस्ताव निर्धारित किया :

“इसका कारण संबंध निर्धारण के निष्पादन में, हमारा विचार है कि राष्ट्रीय प्राधिकरण को यह विश्लेषित करने और तय करने की आवश्यकता है कि क्या उद्योग में, गंभीर क्षति का प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा विचारित परिवर्तनों का कारण बढ़े हुए आयातों को बताया गया है इसके “कारण निर्धारण” मूल्यांकन में राष्ट्रीय प्राधिकरण उस उद्योगकी स्थिति पर अभिप्रेत स्थलप्रद और परिणामनीय प्रकृति के सभी संबद्ध कारकों का मूल्यांकन करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, यदि राष्ट्रीय प्राधिकरण ने बढ़े हुए आयातों से अलग घरेलू उद्योगों को क्षति पहुंचाने वाले कारकों की पहचान की है तो इससे यह सुनिश्चित होगा कि इन कारकों द्वारा हुई कोई भी क्षति बढ़े हुए आयातों द्वारा हुई क्षति नहीं मानी जाती।

**कारण-** संबंध स्थापित करने हेतु कोरिया को दिखाना पड़ेगा कि उसके घरेलू उद्योग को पहुंचने वाली क्षति बढ़े हुए आयात से होता है दूसरे शब्दों में, कोरिया को यह सिद्ध करना होगा एस एम पी पी के आयातों से दूध के पाठड़ और कच्चा दूध का उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचती है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की स्थिति का विश्लेषण करते हुए कोरियन प्राधिकारी का दायित्व बनता है कि बढ़े हुए आयातों को अन्य कारकों द्वारा होने वाला कोई क्षति न होने दे।”

29. ऊपर उल्लिखित मापदंडों के व्यापक मूल्यांकन करने से सिद्ध होता है कि गंभीर क्षति और गंभीर क्षति की आशंका बढ़े हुए आयात के कारण हो रही है। कारण- संबंध का पता लगाने के प्रयोजन हेतु उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले विषयाश्रित और प्रमात्रीकरण-योग्य स्वरूप के सभी संगत कारकों का मूल्यांकन किया गया है। मौजूदा मामले में, इस संबंध में निम्नलिखित संगत हैं-

- (i) आयात की मात्रा में सुनिश्चित रूप से जौर 100 प्रतिशत से 262 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है;
- (ii) आयात का मार्केट शेयर भी 6 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक बढ़ा है और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के मार्केट शेयर में 45 प्रतिशत से 37 प्रतिशत गिरावट आयी है।
- (iii) 2015-16 (पहली तिमाही) के दौरान घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य से कमतर मूल्यों पर आयात के उपलब्ध होने के कारण उपभोक्ता आयात की ओर रुख बदल रहे हैं और जिसके कारण घरेलू उद्योग बढ़ती माल-सूची का सामना कर रहा है और घटते आयात मूल्य घरेलू उद्योगों को उसके मूल्य को कायम रखने से रोक रहे हैं;
- (iv) कम मूल्य पर आयात में बढ़ोतरी के कारण, घरेलू उद्योग भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग/खपत में वृद्धि की दर के मुकाबले में अपना उत्पादन एवं विक्री में वृद्धि करने में असमर्थ हैं;
- (v) लाभधारिता घट गई है तथा आयात में बढ़ोतरी के कारण सर्वाधिक हाल की अवधि में घरेलू उत्पाद को हानि होनी शुरू हो गई।

30. उपरोक्त के मद्देनजर मुझे लगता है कि आयात में बढ़ोतरी एवं घरेलू उद्योग के द्वारा खाई गई गंभीर चोट के बीच प्रत्यक्ष पारस्परिक संबंध है क्योंकि आधार वर्ष 2013-14 के मुकाबले में वर्ष 2015-16 (ए) के दौरान स्पष्ट शब्दों में आयात में लगभग तीन गुण वृद्धि हुई है तथा घरेलू उद्योग का मार्केट शेयर कम हो रहा है जो 45 प्रतिशत से घटकर 37 प्रतिशत हो गया है। प्रतिटन आयात कीमत काफी तेजी से गिरी है। परिणामतः घरेलू उद्योग के लाभ में कमी आई है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आयात में बढ़ोतरी के कारण घरेलू उद्योग को चोट पहुँची है।

#### **(X) विकासशील देश :**

31. विकासशील देशों से आयात की प्रतिशतता की भी जांच की गई है। विचाराधीन उत्पाद का आयात एक से अधिक उन विकासशील देशों से हो रहा है जिनकी भारत में आयात की प्रतिशतता 9 प्रतिशत से अधिक है। अतः दिनांक 14.12.1998 की यथा संशोधित अधिसूचना संख्या 103/98 सीमा शुल्क के अनुसार विकासशील देशों से होने वाले विचाराधीन उत्पाद के आयात पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 ख के उपबंध के अनुसार संरक्षण शुल्क भी लगता है।

#### **(X) नाजुक परिस्थितियां :**

32. सीमा-शुल्क (टैरिफ संरक्षण शुल्क की पहचान एवं निर्धारण) "नाजुक परिस्थितियों" का अर्थ उन परिस्थितियों से है जिनमें इस बात का स्पष्ट साक्ष्य है कि इतनी अधिक मात्रा में एवं ऐसी परिस्थितियों में आयात हुए हैं जिनसे घरेलू उद्योग को गंभीर चोट पहुँचाने अथवा गंभीर चोट होने की आशंका है और अनन्तिम संरक्षण शुल्क लगाने में विलंब से घरेलू उद्योग को अपूरणीय हानि होगी।

33. दिनांक 29.7.1997 की अधिसूचना संख्या 35/97 -एन टी -सीमा शुल्क के द्वारा अधिसूचित सीमा-शुल्क टैरिफ (संरक्षण शुल्क की पहचान एवं निर्धारण) नियमावली 1997 के नियम 9 में निर्दिष्ट है कि महा निदेशक जांच का शीघ्र संचालन करवाएगा तथा नाजुक परिस्थितियों में वह "गंभीर" अथवा 'गंभीर चोट की आशंका' के संबंध में एक प्राथमिक जांच परिणाम दर्ज कर सकता है। जांच के संचालक सिद्धांत सीमा शुल्क (संरक्षण शुल्क की पहचान एवं निर्धारण) नियमावली, 1997 के नियम 6 में उपलब्ध करवाए गए हैं। उक्त नियमावली के नियम 6 एवं 9 को सामंजस्य से पढ़ने

पर यह निष्कर्ष निकलता है कि नियमावली में प्रारंभिक जांच परिणाम के आधार पर अनंतिम संरक्षण शुल्क की शीघ्र सिफारिश का प्रावधान है। उक्त नियमावली के नियम 15 में अंतरीय संरक्षण शुल्क के रिफंड का प्रावधान है यदि जांच की समाप्ति के उपरांत लगाया गया संरक्षण शुल्क पहले से लगाए गए तथा संग्रहित अनंतिम शुल्क से कम हो। वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में यह माना गया है कि विचाराधीन उत्पाद के आयात में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योग के निष्पादन में तीव्र गिरावट के मद्देनजर अंतरिम उपाय अनिवार्य है। चूंकि इस मामले पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है तथा नाजुक परिस्थितियों के मद्देनजर अनंतिम जांच परिणाम जारी किए जा रहे हैं, यह अंतरिम उपाय पूर्णतः घरेलू कानून तथा संरक्षण पर डब्ल्यूटी ओ के समझौते के अनुरूप है।

34. नाजुक परिस्थितियों का होना निर्धारित करने के लिए आयात में बढ़ोतरी तथा घरेलू उद्योग के कमज़ोर निष्पादन पर विचार किया गया है।

(क) वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 (तिमाही-1) के आंकड़ों के तिमाही वार विश्लेषण से ज्ञात होता है कि वर्ष 2014-15 (तिमाही-1) के मुकाबले 2015-16 (तिमाही-1) अवधि के दौरान आयात काफी उच्च स्तर पर रहे हैं तथा इसी अवधि के दौरान आयात की कीमतों में अत्यधिक गिरावट आई है जिससे घरेलू उद्योग की कीमतें नीचे आ गई हैं। वर्ष 2015-16 (तिमाही-1) घरेलू उद्योग की निबल बिक्री नीचे आ गई है जब इसकी वर्ष 2014-15 (तिमाही-1) के दौरान निबली बिक्री से तुलना की जाए तो, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

विवरण	इकाई	2014-15 (क्यू 1)	2014-15 (क्यू 2)	2014-15 (क्यू 3)	2014-15 (क्यू 4)	2015-16 (क्यू 1)
बिक्री की कीमत (सूची बद्ध)	रुपए /एमटी	100	99	101	94	94
धारित औसतन ब्लिकी (सूचीबद्ध)	रुपए /एमटी	100	100	96	90	82
उत्तरान मूल्य (सूची बद्ध)	रुपए /एमटी	100	98	98	90	78
लाभ/(हानि) (सूची बद्ध)	रुपए /एमटी	100	113	41	49	(31)
अंडर कटिंग मूल्य (सूचीबद्ध)	रुपए /एमटी	(100)	(71)	(94)	(94)	(13)

(ख) बिक्री वसूली में उल्लेखनीय कमी के कारण लाभ प्रति एम टी में तेजी से गिरावट आई और वर्ष 2014-15 (क्यू 4) की तुलना में वर्ष 2015-16 (क्यू 1) के दौरान क्षति में बदल गई। क्योंकि घरेलू उद्योग के लिए लाभ पहले ही क्षतियों में बदल गए हैं, अतः यह जरूरी है कि आगे और कोई समय बरबाद किए बिना आयात में प्रवाह को रोका जाए।

(ग) घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि वे भी बहुत से ग्राहकों से विषयगत वस्तुओं को पर्याप्त रूप से निम्न दर पर आपूर्ति करने के लिए प्रतिकूल प्रस्ताव प्राप्त कर रहे हैं। ग्राहक विषयगत वस्तुओं के मूल्य में कमी लाने के लिए चीनी एवं कोरियन आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत मूल्यों का भाव बताते हैं। चीनी एवं कोरियन उत्पादकर्ता जुलाई, 2015 के दौरान 320-350 यूएस डालर प्रति एमटी की रेज में कीमत लगाई है। तदनुसार घरेलू उद्योग सितम्बर—अक्टूबर 2015 की कीमतों में आगे और गिरावट आ रही है। स्पष्ट संकेत है कि बढ़ते आयात ने घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाया है और गंभीर खतरा पहुंचाने के लिए धमकी भी दे रहा है।

(घ) आयात का मार्केट शेयर वर्ष 2013-14 में 6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015-16 (ए) में 12 प्रतिशत हो गया है। घरेलू उद्योग को आयात में प्रवाह के कारण उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोगिता को रोककर रखने के लिए बाध्य कर दिया गया है। घरेलू उद्योग के साथ सामान सूचियां बढ़ रही हैं। इसके अलावा, घरेलू उद्योग वित्तीय क्षतियों का सामना कर रहा है।

(ड.) इस प्रकार प्राथमिक संकल्प दर्शाता है कि जांच की समग्र अवधि के दौरान गिरती यूनिट मूल्यों के साथ आयात में अत्यधिक प्रवाह; घरेलू उद्योग का कमजोर निष्पादन ने गंभीर खतरा पैदा किया है अथवा गंभीर खतरे को धमकी दी है तथा मौजूदा केस में नाजुक परिस्थितियां संस्थापित की हैं।

### (ग) निष्कर्ष

35. घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के विश्लेषण तथा नुकसान माप दंडों के आधार पर यह पाया गया है कि घरेलू उद्योग मार्केट शेयर, लाभ/क्षति, सामान सूची, घरेलू बिक्री की मतों आदि में गिरावट के संबंध में गंभीर खतरे का सामना/गंभीर खतरे की धमकी का सामना कर रहा है। फलस्वरूप घरेलू उद्योग की क्षतियों में विषयगत वस्तुओं का उल्लेखनीय बढ़ते हुए आयात के कारण वृद्धि हुई है। उपरोक्त के मद्देनजर, मैं पाता हूँ कि गंभीर खतरे के विनाश से घरेलू उत्पादकर्ताओं को बचाने के उद्देश्य से तत्काल अनंतिम सुरक्षोपाय शुल्क के लगाने को न्यायोचित ठहराते हुए संकटपूर्ण परिस्थितियों विद्यमान हैं जिससे इससे पार पाना मुश्किल होगा, यदि सुरक्षोपय के अनुप्रयोग में विलंब किया जाता है।

### (घ) सिफारिश :

36. उपरोक्त निष्कर्षों के मद्देनजर यह निष्कर्ष लिया गया है कि भारत में पीयूसी के बढ़ते आयात ने घरेलू उद्योग/पीयूसी के उत्पादकों को गंभीर खतरा पहुंचाया है और गंभीर खतरा पहुंचाने की धमकी दी है। संकटपूर्ण परिस्थितियां मौजूद हैं, जहां अनंतिम सुरक्षोपायों हेतु अनुप्रयोग में कोई विलंब विनाश करेगा जिससे इससे पार पाना मुश्किल होगा, 200 दिनों की अवधि के लिए अनंतिम सुरक्षा शुल्क के तत्काल अनुप्रयोग की जरूरत पैदा होगी, गंभीर खतरे तथा गंभीर खतरे की धमकी का लंबित अंतिम संकल्प/घरेलू उत्पादकों द्वारा पीयूसी की बिक्री की औसत कीमत पर विचार करते हुए (गोपनीय) ब्याज को छोड़कर बिक्री की कीमत पर यथोचित आय, आयात शुल्क का वर्तमान स्तर तथा पीयूसी का औसत आयात मूल्य, 200 दिनों के लिए मूल्यानुसार 20% (बीस प्रतिशत) यथामूल्य की दर पर अनंतिम सुरक्षा शुल्क जिसे घरेलू उद्योग के हित का संरक्षण करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम होने पर विचार किया गया है, पीयूसी के आयात पर लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

### (ड.) आगे की प्रक्रिया :

37. विभिन्न पार्टियों द्वारा प्रदान की गई सूचना सत्यापन के अध्यधीन हो सकती है जहां जरूरी हो, जिसके लिए वे अलग से सूचित करेंगे।

38. अंतिम संकल्प करने से पूर्व कुछ समय बाद एक जन सुनवाई का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तारीख की अलग से सूचना दी जाएगी।

[फा. सं. डी-22011/26/2015/पार्ट.-I/786]

विनय छाबड़ा, महानिदेशक

**MINISTRY OF FINANCE**  
**[DIRECTOR GENERAL (SAFEGUARDS)]**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th September, 2015

**Subject:-Safeguard investigation concerning imports of “Hot-rolled flat products of non-alloy and other alloy Steel in coils of a width of 600 mm or more” into India. – Preliminary findings-Reg**

**G.S.R. 690(E).**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 and the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 thereof;

**(A) Procedure**

1. An application has been filed before me on 27th July, 2015 under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 by M/s. Steel Authority of India Limited; M/s. Essar Steel India Limited, and M/s. JSW Steel Limited through M/s. Lakshmi Kumaran & Sridharan Attorneys, New Delhi, for imposition of Safeguard Duty on imports of “**Hot-rolled flat products of non-alloy and other alloy Steel in coils of a width of 600 mm or more**”, hereinafter referred to as ‘PUC’ (Product under consideration) into India to protect the domestic producers of PUC against serious injury/threat of serious injury caused by the increased imports of PUC into India. The domestic industry has also requested for imposition of provisional safeguard duty in view of steep deterioration in performance of the domestic industry as a result of increased imports of product under consideration.
2. In order to satisfy the requirements under Rule 5 of the said Safeguard Rules, the information presented by the applicant was got verified by on-site visits to the plants of the domestic producers to the extent considered necessary. The non-confidential version of verification report is kept in the public file. Having satisfied that the requirements of Rule 5 were met with, safeguard investigation against imports of PUC into India was initiated vide notice of initiation dated 7th September, 2015 and published in the Gazette of India, Extraordinary on the same day.
3. A Copy of the Notice of Initiation dated 7th September, 2015 along with copy of non-confidential version of the application filed by the domestic industry were forwarded to the Central Government in the Ministry dealing with Commerce and other Ministries concerned, Governments of major exporting countries through their embassies in India, and the Interested Parties mentioned in the application filed by domestic industry, in accordance with Rule 6(2) and 6(3) of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997.
4. Questionnaires were sent to the known interested parties as per the information available with request to make their views known in writing within 30 days of the initiation notice.

**(B) Preliminary Observation and Findings of the Director General (Safeguards) :**

5. I have carefully gone through the application filed by the domestic industry and the records of verification visit conducted by the officers of the Directorate General of Safeguards.

**(I) The product under Consideration (PUC):**

The product under consideration is “**Hot-rolled flat products of non-alloy and other alloy Steel in coils of a width of 600 mm or more**” hereinafter referred to as ‘PUC’ (Product under consideration) classifiable under Chapter 72 of the Customs Tariff Act, 1975, under tariff heading 7208 and tariff item 72253090. The applicant has claimed that these products are not further worked than hot-rolled and are flat products of iron, alloy or non-alloy steel, in prime or non-prime condition having ‘as-rolled’ edge or ‘trimmed’ edge or ‘slit’ edge. These products may be pickled or non-pickled (with or without skin-pass or tempering), slit or non-slit and having nominal width of greater than or equal to 600 mm. These products may be as-rolled or thermo-mechanically rolled or thermo-mechanically controlled rolled or controlled rolled. These products may have patterns in relief derived directly from rolling. These products may have been subjected to various processing steps like pickling, oiling, rewinding, temper rolling, heat treatment, etc.

The following are not included in the scope of the product under consideration:

- (a) Hot-rolled flat products of steel with nominal width less than 600 mm;
- (b) API grade steel;
- (c) Silicon electrical steel;
- (d) Hot-rolled flat products of steel of spring steel quality;
- (e) Hot-rolled flat products of steel which are electrolytically plated or coated with zinc;
- (f) Hot-rolled flat products of steel otherwise plated or coated with zinc; and
- (g) Hot-rolled flat products of stainless steel.

**(II) Domestic Industry:**

6. Section 6(b) of the Customs Tariff Act 1975 defines domestic industry as follows:
- (b) "Domestic industry" means producers -
- as a whole of the like article or a directly competitive article in India; or*
  - whose collective output of the like article or a directly competitive article in India constitutes a major share of the total production of the said article in India.*
7. The application has been filed by M/s. Steel Authority of India Limited; M/s. Essar Steel India Limited, and M/s. JSW Steel Limited through M/s. Lakshmi Kumaran & Sridharan Attorneys, New Delhi. They have claimed that their production together accounts for more than 50% of the total production of PUC in India and it represent a major proportion of Indian production of the product under consideration in the country and thus have the standing to file the present application.
8. After taking into account the information on record, it is determined that production of the domestic producers filing the application and who have provided relevant information constitutes a major share of the total production of the said article in India. Accordingly, they constitute Domestic Industry as per Section 6(b) of the Customs Tariff Act 1975.

**(III) Period of Investigation (POI):**

9. The Customs Tariff Act, 1975, the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard duty) Rules, 1997, the Agreement on Safeguard and the Article XIX of GATT do not specifically define what the Period of Investigation should be. From several case laws on safeguard measures, it is clear that neither the domestic laws on Safeguard nor Agreement on Safeguard and Art. XIX of GATT provides specific guidelines on the period of investigation except the fact that the relevant investigation period should be sufficiently long to allow conclusion to be drawn on increased import and serious injury. The Period of investigation in this case has been taken from 2013-14 to 2015-16 (Annualised) which is long enough to take into consideration the market conditions and to ascertain the need, if any, of imposition of Safeguard Duty.

**(IV) Source of Information:**

10. The transaction wise import data for the 'PUC' has been taken from International Business Information Services (IBIS), as provided by the domestic industry from 2013-14 to 2015-16 (Q1) and same has been taken into consideration for analysis. The domestic data from 2011-12 to 2015-16 (Q1) has been submitted by the domestic industry and the same has been verified by on-site visit by the department on the basis of excise records and other records maintained in the units to the extent deemed necessary.

**(V) Confidentiality of Information submitted:**

11. The domestic industry has provided some information on confidential basis and sought confidentiality on the information /data submitted. The domestic industry provided non confidential version of the application for safeguard measure as per the provisions of Safeguard Rules 1997 and Trade Notice No. SG/TN/1/97 dt. 06.09.1997. Further the domestic industry has submitted reasons for seeking confidentiality at the time of filing the application.
12. Rule 7 of the Safeguards Rules, 1997 and Art. 3.2 of WTO Agreement on Safeguards also provide for confidentiality. The applicant is not required to disclose such information which is confidential information of the company, disclosure of which can cause serious prejudice to the business interests of the company, which is not in public domain and which the applicant has not disclosed before public at large in the past. Accordingly confidentiality, as prayed for by the domestic industry, is granted.

**(VI) Increased Imports (Absolute & in relative terms):**

13. 'PUC' is imported into India from various countries. The imports of 'PUC' have shown an increasing trend in absolute terms as well as in relative terms during the period as shown in table below:-

Financial Year	Total Imports (MT)	Index	All India Production (MT)	Import with respect to all India production (%)
2013-14	1292099	100	25510777	5
2014-15	2540114	197	26395795	10
2015-16 (Q1)	844840		6646258	
2015-16 (A)	3379360	262	26585032	13

**(VII) Unforeseen development:**

14. It is noted that there is no express obligation/requirement on the Director General (Safeguards) to analyse unforeseen circumstances as there is no specific requirement either in the Indian Rules, on the methodology that should be followed for analyzing unforeseen developments or in the WTO Agreement on Safeguards, which also does not make any prescription with regard to the methodology that should be followed or the parameters that must be met in deciding unforeseen developments. The Agreement on Safeguards read with Article XIX of GATT, however, obligates the national authorities to examine the “unforeseen developments” which led to the serious injury to the Domestic Industry. It is understood that this Directorate has consistently been examining the issue of “unforeseen developments” in its investigations. It is, therefore, considered important to examine the unforeseen developments or circumstances which have led to increased imports.
15. The Appellate Body in Argentina – Footwear (EC case) held that the phrase Unforeseen Developments means the developments which were unexpected. ‘Unforeseen Developments’ require that the developments which led to a product being imported in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to domestic producers must have been ‘unexpected’. The Body in the same case noted a GATT panel report which held that the development must have been unforeseen at the time of tariff negotiation. The Appellate Body in Korea-Dairy case held that unforeseen developments are developments not foreseen or expected when member incurred that obligation.
16. The Appellate Body, in Argentina — Footwear (EC), then held that the requirement of “Unforeseen Developments” did not establish a separate “condition” for the imposition of safeguard measures, but described a certain set of “circumstances”:
17. The panel on US- Steel Safeguards<sup>1</sup> concluded that the confluence of several events can unite to form the basis of an unforeseen development:
 

*The United States argues that the robustness of the US dollar was a development which combined with the other developments, namely, the currency crises in Asia and the former USSR and the continued growth in steel demand in the United States' market as other markets declined, lead to increased imports.”*
18. The applicant has pointed out that Steel manufacturers in a number of countries including China PR, Russia, Ukraine have developed huge capacities to cater to demand of steel by developed countries and rest of the world. Most of the developed countries that were traditionally the biggest importers of steel such as United States and the European Union have reduced their dependence on imported steel. This development adversely affected exports of steel from China PR, Russia, Ukraine etc. to developed countries. Manufacturers in these countries had to think of ways to dispose off their production. India happened to be the natural choice for these manufacturers for multiple reasons.
19. World crude steel capacity at 2351 million tons as on 31 December, 2014 has reached a level far in excess of global demand by almost 30% resulting in growing urge to export the surplus steel to countries like India that have good demand.
20. India, with relatively better demand prospects (domestic demand up by 3.1%) and high domestic prices, has remained an attraction for these steel surplus economies to channelize their excess capacities.
21. Russia has increased its exports to India. As per a report by a reputed journal Steel 360, Russian steel exporters have been experiencing high realization for their exports due to their currency that has weakened in the recent past. This has led to an export push for Russian steel in India. Further, the Russian exporters have a restricted access to traditional markets like the European Union and Ukraine resulting in export push to India.
22. Ukraine’s currency Hryvnia witnessed sharp depreciation of about 60% in 2014 alone. This was a result of political unrest in Ukraine due to Russia’s intervention. Due to long period of unrest in Ukraine, its economy contracted and its currency sharply depreciated to US dollar. However, depreciation in Ukraine’s currency helped its steel producers/exporters to leverage their low priced exports to put further pressure on the global steel market. It is well documented in many leading international newspapers and journals how Ukraine has joined Russia and China PR to drive down steel prices and divert its surplus steel to countries with good demand. It is documented that Ukraine will continue this trend even in 2015.
23. China PR is experiencing weak domestic demand. Infrastructure sector, mainly housing, which has been the biggest consumer of steel in China PR is going through a slowdown. Manufacturers in China PR can no longer dispose off their production in the domestic market. This situation is likely to remain unchanged in the short term and Chinese steel use will continue to record a negative growth of -0.5% in 2015 and 2016. As a result, exports to countries like

---

<sup>1</sup>Para 86 of Korea Dairy case Appellate Body Report Of WTO 36

India is a natural choice as demand of steel has been on the rise in India. Such intrinsic factors in China PR led to sudden surge of imports from China PR.

24. On examining the data/evidences given, it is noticed that producers in China PR, Russia, Ukraine and other countries are sending PUC in the Indian market as India, with relatively better demand prospects and high domestic prices, has remained an attraction for these steel surplus economies to channelize their excess capacities. The report published in **World Steel Dynamics** states that “effective capacity figure for early 2015 is 1055 million tones for the non-Chinese industry and 991 million tones for China, a total of 2.05 billion tones. When compared to steel production in 2014 of 1.66 billion tones, there is 382 million tones of excess global steel making capacity”. Accordingly, In view of above and in view of the evidences produced, I observe that the excess capacities present in the major exporting countries and increasing Indian demand/apparent consumption of PUC are the reason for increase in imports. It is, therefore, seen that the above reasons cited by the Domestic Industry constitute unforeseen development.

#### (VIII) Serious Injury and Threat of Serious Injury

25. **Serious Injury:** The applicant have claimed that the increased imports of ‘PUC’ have caused and are threatening to cause serious injury to the domestic producers of ‘PUC’ as indicated by the following factors:

(a) **Production:** The production of the domestic industry remained at the same level during 2013-14, 2014-15 and 2015-16 (Annualised) as shown in the following table:-

YEAR	Production of DI (MT)	Index
2013-14	17881187	100
2014-15	17836937	100
2015-16(Q1)	4456795	
2015-16(A)	17827180	100

(b) **Market Share of domestic producers in domestic demand:** Market share of the applicants has fallen in the most recent period. Applicants had a market share of 45% in 2013-14 which fell to 37% during 2015-16 (A). During the same period, the market share of import increased from 6% to 12%, as shown below:-

Financial Year	Total Import (MT)	Sales of DI (MT)	Sales of other Indian Producers (MT)	Captive sale of DI(MT)	Captive sale of Others (MT)	Total Demand (MT)	Market Share (%)	DI	Import
2013-14	1292099	10342565	2994323	4274000	4000724	22903711	45	6	
2014-15	2540114	9949214	3298273	5019741	4615864	25423206	39	10	
2015-16(Q1)	844840	2589929	1065972	1321497	1180681	7002919			
2015-16(A)	3379360	10359716	4263888	5285988	4722724	28011676	37	12	

(c) **Productivity & Employment:** The trend of employment and productivity remained same throughout the period as shown in the table below:-

Financial Year	No. of Employees (Indexed)	Productivity per employee (MT) (Indexed)
2013-14	100	100
2014-15	100	100
2015-16(Q1)	100	
2015-16(A)	100	100

(d) **Capacity Utilisation:** The capacity utilisation remained same during the period 2013-14 to 2015-16(A) as evident from the table below:

Financial Year	Installed Capacity (MT)	Capacity Utilisation (%)
2013-14	23568996	76
2014-15	23568996	76
2015-16(Q1)	5884372	
2015-16(A)	23537488	76

(e) **Profit/loss** – The profitability of the domestic industry has declined sharply in 2015-16(Q1) and the domestic industry recorded losses as shown in the following table:-

Financial Year	Profitability (Rs. /MT) (Indexed)
2013-14	100
2014-15	135
2015-16(Q1)	(55)

(f) **Inventory**- The table below depicts the inventory levels which have witnessed an increase from 100 points in 2013-14 to 103 points in 2015-16(A).

Financial Year/Quarter	Inventory (MT)	Inventory (MT) (Indexed)
2013-14	636879	100
2014-15	648290	102
2015-16(Q1)	657099	103

(g) **Price depression:** It is noticed from the table that the domestic industry was always under consistent pressure to either reduce their prices to match the import prices or to hold on to their prices. The penetration of increased imports at an unprecedented high level was such that even after reducing the prices, the domestic industry was not able to keep on to its production, sales and market share. This has resulted into losses during 2015-16(Q1) for the domestic industry.

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16(Q1)
Cost of sales (Indexed)	Rs/MT	100	97	92
Weighted average sales realisation (Indexed)	Rs/MT	100	99	84
Landed Value(Indexed)	Rs/MT	100	94	77
Profit/(Loss) Indexed	Rs/MT	100	135	(55)

26. In view of the above, it is seen that there is all around deterioration in the financial parameters of the domestic industry and the domestic industry has suffered serious injury and immediate protection is required in the form of the safeguard duties with a view to save the domestic industry from further injury.
27. As may be seen from the above, a threat of serious injury is also present in the current investigation. There is a huge increase in imports over the period of investigation which has caused serious injury to the domestic industry and in all likelihood, the imports of the PUC will further increase and continue to threaten the domestic industry with serious injury. The market share of domestic industry decreased from 45% in 2013-14 to 37% during 2015-16(A) whereas during the same period, the market share of import increased from 6% in 2013-14 to 12% in 2015-16(A) which is a cause of concern.

#### **(IX) Causal Link between Increased Import and Serious injury or Threat of Serious injury:**

28. The Panel on Korea — Dairy set forth the basic approach for determining “causation”:

*In performing its causal link assessment, it is our view that the national authority needs to analyse and determine whether developments in the industry, considered by the national authority to demonstrate serious injury, have been caused by the increased imports. In its causation assessment, the national authority is obliged to evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry. In addition, if the national authority has identified factors other than increased imports which have caused injury to the Domestic Industry, it shall ensure that any injury caused by such factors is not considered to have been caused by the increased imports.*

*To establish a causal link, Korea has to demonstrate that the injury to its Domestic Industry results from increased imports. In other words, Korea has to demonstrate that the imports of SMPP cause injury to the Domestic Industry producing milk powder and raw milk. In addition, having analyzed the situation of the Domestic Industry, the Korean authority has the obligation not to attribute to the increased imports any injury caused by other factors.<sup>2</sup>*

29. A comprehensive evaluation of parameters enumerated above demonstrates that serious injury and threat of serious injury is being caused by increased imports. For the purpose of determining causation, all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of the industry have been evaluated. In the instant case, the following are relevant in this regard –

- (i) **The volume of imports has increased significantly from 100% to 262% in absolute terms ;**
- (ii) **Market share of imports has increased from 6% to 12% and, consequently, market share of the Domestic Industry has declined from 45% to 37%;**
- (iii) **As the imports are available at prices lower than the selling price of Domestic Industry during 2015-16(Q1), the consumers are switching over to imports due to which the Domestic Industry is faced with rising inventory and the decreasing import prices are preventing the Domestic Industry from sustaining its prices.;**
- (iv) **Due to increased imports on low prices, the Domestic Industry is unable to increase its production and sales as compared to the rate of increase in demand/consumption of product under consideration in India;**
- (v) **The profitability has declined and DI started to incur losses in the most recent period due to increased imports.**

30. In view of the above I find that there is a direct correlation between the increase in imports and serious injury suffered by the domestic industry as import in absolute term increased more than two and a half times during the year 2015-16(A) as compared to base year 2013-14 and domestic industry is losing market share which has declined from 45 % to 37 %. The import price per ton has declined sharply. Consequently, the domestic industry has suffered

<sup>2</sup> [Panel Report on Korea – Dairy](#), paras. 7.89-7.90

losses in the recent past. It is, thus, evident that injury to the domestic industry has been caused by the increased imports.

**(X) Developing Nations:**

31. The percentage of imports from developing nations has also been examined. The import of the product under consideration is originating from more than one developing nation whose aggregate percentage of import into India is more than 9%. Therefore, in terms of Ntn.103/98 cus dated 14-12-98 as amended, the import of product under consideration originating from developing nations will also attract Safeguard Duty in terms of proviso to Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975.

**(XI) Critical Circumstances:**

32. As per Rule 2(b) of Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 the “Critical circumstances” means circumstances in which there is clear evidence that imports have taken place in such increased quantities and under such circumstances as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry and delay in imposition of provisional safeguard duty would cause irreparable damage to the domestic industry.
33. The Rule 9 of Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 notified vide Notification No. 35/97-NT-Customs dated 29.07.1997 prescribes that the Director General shall proceed expeditiously with the conduct of the investigation and in critical circumstances, he/she may record a preliminary finding regarding “serious” or “threat of serious injury”. The principles governing investigations have been provided in the Rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997. The harmonious reading of Rules 6 and 9 of the said Rules leads to a conclusion that the Rules provide for expeditious recommendation of provisional Safeguard duty based on preliminary findings. The Rule 15 of the said Rules provide for refund of differential Safeguard duty in case safeguard duty imposed after conclusions of the investigations is lower than the provisional duty already imposed and collected.
34. The surge in import, poor performance of the domestic industry have been considered in order to determine the existence of critical circumstances.

- (a) The quarter wise analysis of the data for 2014-15 and 2015-16(Q1) indicates that imports have remained at significantly higher levels during the period 2015-16(Q1) as compared to 2014-15(Q1) and the import prices have come down drastically over the same period leading the domestic industry’s prices downwards. The net sales realisation of the domestic industry came down during 2015-16(Q1) when compared with the net sales realization during 2014-15(Q1) as shown below:-

Particulars	Unit	2014-15 (Q1)	2014-15 (Q2)	2014-15 (Q3)	2014-15 (Q4)	2015-16 (Q1)
Cost of sales (Indexed)	Rs/MT	100	99	101	94	94
Weighted average sales realisation (Indexed)	Rs/MT	100	100	96	90	82
Landed Value(Indexed)	Rs/MT	100	98	98	90	78
Profit/(Loss) Indexed	Rs/MT	100	113	41	49	(31)
Price undercutting(Indexed)	Rs/MT	(100)	(71)	(132)	(94)	(13)

- (b) Due to a significant decline in sales realisation, profits per MT have declined sharply and turned into losses during 2015-16(Q1) as compared to 2014-15(Q4). As the profits have already turned into losses for the domestic industry, it is necessary to arrest the surge in imports without any further loss of time.
- (c) The domestic industry has claimed that they are also receiving counter offers from many customers to supply the subject goods at substantially lower prices (lower than cost of production). The customers quote the prices offered by Chinese and other suppliers to force the reduction in prices of subject goods. The Chinese and Other producers have offered a price in the range of USD 320-350 per MT during the month of July 2015 for supplies to be effected in September-October,2015. Accordingly, the prices of the domestic industry are spiraling down further. There is clear evidence that increased imports have caused and are also threatening to cause serious injury to the domestic industry.
- (d) The market share of import has risen from 6% in 2013-14 to 12% in 2015-16(A). The domestic industry has been forced to keep production, Sales , capacity utilization on hold due to surge in imports. Inventories with the domestic industry are rising. Further, the domestic industry is facing financial losses.

- (e) The preliminary determination thus shows that excessive surge in import with falling unit price during the entire period of investigation; poor performance of the Domestic industry has caused serious injury or threat of serious injury and constitute critical circumstances in the instant case.

**(C) Conclusion:**

35. On the basis of analysis of the application filed by the domestic industry and the injury parameters it is observed that the domestic industry is suffering serious injury/threat of serious injury in respect of market share, profits/losses, inventory, decline in domestic selling prices etc. As a result, domestic industry have incurred losses on account of significant increased imports of the subject goods. In view of the above, I find that critical circumstances exist justifying imposition of provisional safeguard duties immediately in order to save the domestic producers from damage of serious injury which it would be difficult to repair, if the application of safeguard measure is delayed.

**(D) Recommendation:**

36. In view of the findings above, it is concluded that increased imports of PUC in to India have caused and threatened to cause serious injury to the domestic industry/ producers of PUC. There exist critical circumstances, where any delay in application for provisional Safeguard measures would cause damage which it would be difficult to repair, necessitating immediate application of provisional Safeguard duty for period of 200 days, pending final determination of serious injury and threat of serious injury. Considering the average cost of sales of PUC by the domestic producers (confidential), a reasonable return on cost of sales excluding interest, the present level of import duties and present average import prices of PUC, provisional Safeguard Duty at the rate of 20% (Twenty percent) ad valorem for 200 days which is considered to be the minimum required to protect the interest of domestic industry, is recommended to be imposed on imports of PUC.

**(E) Further Process:**

37. The information provided by various parties may be subjected to verification where necessary, for which they will be informed separately.
38. A public hearing will be held in due course before making a final determination, for which the date will be informed separately.

[F. No. D-2011/26/2015/Pt.-I/786]

VINAY CHHABRA, Director General